देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 10.07.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में कल से शुरु हो रही कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी।
- कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने पोषण ट्रैकर ऐप की समीक्षा की। जिले में कुपोषण की स्थिति सुधारने पर बल दिया।
- पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया। आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कांवड़ यात्रा

प्रदेश में कल से शुरु हो रही कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ के नियमों का पालन कराने के साथ ही यात्रा को व्यवस्थित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मार्गों पर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रियों से कांवड़ के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है।

भूमि धोखाधड़ी

कुमाऊं मंडल में भूमि धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। समिति ने तय किया कि भूमि खरीदने करने से पहले हर संभावित खरीददार को संबंधित तहसील में आवेदन कर भूमि की जांच करवाकर स्थिति स्पष्ट करवानी होगी, ताकि उसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सके। बैठक में सामने आया कि कई प्रकरणों में एक ही भूमि को दोबारा बेचा जा रहा है या खसरा नम्बर भिन्न दर्शाकर दूसरे भू–भाग पर कब्जा दिलाया जा रहा है। यहां तक कि कई विक्रेताओं द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिससे विवाद और ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस निर्णय के अनुपालन के लिए मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही आम जनता को भी इस प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश दिये हैं, ताकि भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

प्रतिनिधिमंडल भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बदरी–केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और समग्र प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के समर्पित कार्यों के परिणाम स्वरूप श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान न केवल बेहतर सुविधा मिली, बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी बना रहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के संतुलन के साथ संचालित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा से सुखद अनुभव लेकर लौटे और उत्तराखंड की संस्कृति व सेवा भावना की सकारात्मक छवि देश–दुनिया में जाए।

ऑपरेशन लगाम

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने, रैश ड्राइविंग, स्टंट करने वालों और मॉडीफाइड साइलेंसर या हूटर लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ "ऑपरेशन लगाम" के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में सभी प्रभारी अपने–अपने थाना क्षेत्रों में "ऑपरेशन लगाम" के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक दून पुलिस ने 425 चालान किए हैं। साथ ही डेढ लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है, जबकि नियम तोड़ने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पोषण ट्रैकर ऐप

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में पोषण ट्रैकर ऐप की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चिन्हित कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की संख्या, स्वास्थ्य स्थिति और सुधार के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पोषण ट्रैकर पोर्टल पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का डेटा समयबद्ध रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा चिन्हित कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जा रहे संपूरक पोषण आहार की गुणवत्ता व मात्रा, मानक अनुसार हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद क्षेत्र भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति, कार्य संचालन, उपस्थिति रजिस्टर और गतिविधियों की निगरानी करें। उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन व ऊंचाई की नियमित माप, संपूरक पोषण और आहार की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने के भी निर्देश दिए।

पुस्तकालय निरीक्षण

पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला मुख्यालय स्थित जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया और कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक व सुविधायुक्त बनाकर विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पुस्तकों की सूची नहीं पाए जाने पर नाराज़गी जताते हुए 14 दिन के भीतर पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल कैटलॉग बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पाठकों की सुविधा के लिए फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराने और सामूहिक चर्चा के लिए एक समर्पित कॉन्फ्रेंस रूम विकसित करने को भी कहा। साथ ही उन्होंने ई–लाइब्रेरी की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिये। विद्यार्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने पुस्तकालय की समय–सारणी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को अधिक समय तक अध्ययन की सुविधा मिल सके। उन्होंने पुस्तकालय को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए फर्नीचर सुधार और अन्य आधुनिकीकरण कार्यों को शीघ्र शुरू करने पर भी जोर दिया।

चुनाव प्रशिक्षण पंतनगर

ऊधमसिंहनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पंतनगर में दो पालियों में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी कार्मिकों को व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है।

यूसीसी चमोली

समान नागरिक संहिता– यूसीसी के तहत चमोली जिले में अब तक 13 हजार 724 दंपति अपना विवाह पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 219 आवेदनों की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि गत 27 जनवरी से प्रदेश में यूसीसी लागू की गई है, जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क तय किया गया था। वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से गत 27 जनवरी से पहले हुई शादियों के पंजीकरण पर आगामी 26 जुलाई तक शुल्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि यूसीसी में विवाह और अन्य पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। उन्होंने आम जनता से निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए जल्द पंजीकरण कराने का आह्वान किया है।